

प्रेषक,

निधि मणि त्रिपाठी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,
(तकनीकी शिक्षा एवं वित्त)
उत्तराखण्ड शासन।

2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2-आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं
मण्डल, नैनीताल।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 27 नवम्बर, 2014

विषय:-राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित नीति में संशोधन (मात्र पर्वतीय क्षेत्र हेतु) किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-309/XXIV(3)-3(33)/2014 दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के द्वारा नीति/मानक का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के संगत अंशों/बिन्दुओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क.स.	पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 05.09.2014 में निर्धारित मानक	शासनादेश दिनांक 05सितम्बर, 2014 में(संशोधन उपरान्त) निर्धारित मानक
1.	पर्वतीय क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि(अधिकतम तीन समीपवर्ती स्थानों पर 05 किमी० के भीतर) निर्मित क्षेत्र 15,000 वर्ग मीटर।	पर्वतीय क्षेत्र में 2.5 एकड़ भूमि।
2.	प्रस्तावक संस्थान के प्रवर्तकों (Promoters) की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रु. 10.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति (Net worth) कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा-चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट (इस आशय का शपथ-पत्र)।	प्रस्तावक संस्थान के प्रवर्तकों (Promoters) की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रु. 3.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति (Net worth) कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा-चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट (इस आशय का शपथ-पत्र)।
2.	प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवं वित्त के स्रोतों का विवरण। संस्था के बैंक खाते में रु. 7.5 करोड़ जमा होना आवश्यक होगा।	प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवं वित्त के स्रोतों का विवरण। संस्था के बैंक खाते में रु. 2.00 करोड़ जमा होना आवश्यक होगा।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीया,

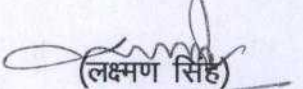
(निधि मणि त्रिपाठी)
सचिव

संख्या :- 649/XXIV(3)-3(33)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो, ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली- 110021
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 20.11.2014 के क्रम में।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
9. समिति के समस्त सदस्यगण।
10. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
12. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव